

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.1054 of 2020

=====

M/s Alectra Construction Ltd. through its director, Shri Dhananjay Kumar,
S/o Sri Anil Kumar Singh, Sex- male, Aged about 39 years, having its
registered office at Ward No. 3, New Colony, Dharampur, Samastipur-
848101.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Water Resource
Department, Govt. of Bihar, Sichayee Bhawan, Patna.
2. The Joint Secretary, Water Resource Department, Govt. of Bihar, Sichayee
Bhawan, Patna.
3. The Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Bihar, Sichayee
Bhawan, Patna.
4. The Chief Engineer, Water Resources Department, Sichayee Bhawan, Patna.
5. The Chief Engineer, WRD, Flood Control and Drainage, Samastipur.
6. The Superintendent Engineer, Flood Control Circle, Samastipur.
7. The Executive Engineer, Flood Control Division, Rosera, Distt. Samastipur.
8. The Assistant Engineer, Flood Control Sub-Division, Rosera, Distt.
Samastipur.

... .. Respondent/s

=====

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr.Kumari Rashmi, Adv Mr. Suresh Pd. Singh No. 1, Adv
For the Respondent/s	:	Mr.Vinay Kriti Singh (GA2)

=====

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE S. KUMAR



ORAL JUDGMENT
(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

Date : 20-09-2022

Heard learned counsel for the parties.

Petitioner has prayed for the following relief(s):-

- i. For quashing the NIT No.01SBD/2019-20 dated 22/11/2019 issued by the respondent No.7 for raising, strengthening and Paccakaran of balance work from Km 85.00 to 98.00 km on the left embankment of River Budhi Gandak and further for staying implementation of Said NIT till disposal of this application, under the specific reason that for the same work, earlier the respondents have Issued NIT and keeping in executed agreement No.2/SBD/2017-18, allotting tender to the petitioner and till date account of the earlier work is not settled nor final measurement is made, as such no fresh work could be allotted through the instant NIT till settling the earlier account, as still huge construction materials, plant & machineries are lying on the works site, apart from that unless final measurement of balance work be ascertained, how the fresh work order could be issued, hence in view of the matter, the NIT or its consequential orders could not be operated, as it will put the petitioner under irreparable loss, in fact to grab the amount of work done, this drama of NIT is played by the to hide their own irregularities/illegalities. Hence it may be quashed.

Our attention is being invited to the order dated 15.09.2021, passed by the Appellate Authority whereby the order dated 08.03.2021 passed by the competent authority debarring the petitioner stands quashed and set aside. The order



passed by the Appellate Authority is Annexure-S/17, which has been quoted hereiunder:-

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

संकेत सं०- ११/निविदा-०६-०९/२०१८- पटना, दिनांक

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निराकरण, जल संसाधन विभाग, सगरतीपुर प्रक्षेत्रधीन बूँदो गडक बायीं तटबंध के कि०मी० ३६.०० से कि०मी० ३९.०० के बीच बाढ़ वर्ष २०१६ के पूर्व सुवर्धन, सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण कार्य (एकराशनाम संख्या-०२३८०/२०१७-१८ तथा एजेन्डा संख्या-१४४/१४९) एवं बूँदो गडक बायीं तटबंध के कि०मी० १२९.७० से कि०मी० १४७.०० के बीच जिलेवा से विरौली स्थल तक तटबंध पर सड़क पक्कीकरण कार्य (एकराशनाम संख्या-०३३८०/२०१७-१८ तथा एजेन्डा संख्या-१४४/१४०) में अतिशय विलम्ब के लिए उक्त कार्यों से संबंधित संपेक्क एलेक्द्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, सगरतीपुर को आदेश जाफांक-३३७१ दिनांक ०४.०९.२०१८ द्वारा अगली निविदा में माग लेने से बंघित/दिबार किया गया था। इसके विरुद्ध संपेक्क द्वारा गाननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या २२८४७/२०१८ एवं सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-२३०३०/२०१८ में दिनांक २३.०७.२०१९ को पारित न्याय निर्णय में दिवार आदेश को Set Aside करतो हुए Fresh Order पारित करने का आदेश दिया गया।

उक्त न्याय-निर्णय के अनुपालन के क्रम में संबंधित मुख्य अभियंता से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुरासा के आलोक में संपेक्क मे० एलेक्द्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ग्राम-न्यू कॉलोनी, धर्मपुर, पो० जिला-समस्तीपुर, पिन-८४८१०१ (नि०सं०- ६४/२०१७) प्रधान श्रेणी को विभागीय आदेश जाफांक-१७३ दिनांक ०८.०३.२०२१ द्वारा दस वर्षों के लिए काली सूची में खला गया है।

इसके विरुद्ध अपीलार्थी संपेक्क द्वारा समर्पित अपील अन्तर्वेदन पर हुए सुनवाई में मुख्यतः दो सभ्य उभर कर प्रकाश में आय है जो निम्नवत है :-

- शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर स्टोन पिन्स के रैक का उपलब्ध नहीं होना तथा,
- Machinery Mobilization Advance का समय प्राप्त नहीं होना।

उपर्युक्त कोंडेका-१ के संदर्भ में कार्तीकरण आदेश में उल्लेखित है कि नियमानुसार संपेक्क को निविदा अपलोड करने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य से अवगत होना चाहिए था। इस संदर्भ में अपीलार्थी का कहना है कि कार्य स्थल के निरीक्षण का तात्पर्य स्टोन पिन्स के रैक के निरीक्षण से नहीं है। अपीलार्थी का यह कथन मान्य योग्य प्रतीत होता है कि सी०डी०आर० में शेखपुरा स्टोन पिन्स के रैक के बन्द रहने का उल्लेख नहीं किया गया है।



कॉन्ट्रैक्ट-2 के संदर्भ में जालीकरण आदेश में उल्लेख किया गया कि संदेक द्वारा दो-दो-संलग्न नहीं करने के कारण Machinery Mobilization Advance संभलवा नहीं किया जा सका। जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कहा गया कि प्रकल्पता बैंक गारंटी की सावधानी अति-उत्प्रेक्षा में स्थिति स्पष्ट हुए बिना सी०जी० संलग्न नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त कॉन्ट्रैक्ट-1 एवं 2 में वर्णित तथ्यों के आलोक में संदेक से० एलेक्स करटुआन लिमिटेड, ग्राम-बू, कॉलेजी, धर्मपुर, पो० वि०-समस्तीपुर, पिन-848101 (नि०सं०-54/2017) प्रकल्प क्षेत्री को जालीकरण आदेश जापान 773 दिनांक 08.03.2021 द्वारा जारी गए सूची से मुक्त किया जाता है। इस मामले में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लिखे गए अन्य निर्णय इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।


(संजीव कुमार)

संजीव-सह-अपीलीय अधिकारी

जापान 3873, पटना/दिनांक 16.9.2021
प्रतिनिधि - श्री संजय कुमार, प्रबंध निदेशक, एलेक्स करटुआन लिमिटेड, ग्राम-बू, कॉलेजी, धर्मपुर, पो० वि०-समस्तीपुर, पिन-848101 को सूचनाएं भेजिए।
(संजय कुमार सिंह)
संलग्न के अन्तर्गत संजय

We are informed that the petitioner has preferred petition before the Tribunal constituted under the provisions of the Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008. It is prayed that the hearing of the said petition be expedited.

State cannot have any objection to the same.

It is a matter of record that post recession of the petitioner's contract which was in the year-2019, certain amount



deposited by the petitioner as security amount also stands forfeited. It is also alleged that prior to the allotment of work to 3rd party, no measurements were taken nor account of the petitioner was settled.

Well, all these are issues, which are pending consideration before the Tribunal and can be best adjudicated by the final fact finding adjudicatory authority.

As prayed for, the petition is disposed of with direction to the Tribunal to expedite hearing in the petitioner's application and have the same decided within a period of six months from the date of placing of the order passed by this Court.

Needless to add, the Tribunal shall also account for the order passed by the Appellate Authority vide memo no. 3003 dated 16.09.2017 (Annexure-S/17).

Interlocutory application, if any, shall also stand disposed of.

(Sanjay Karol, CJ)

(S. Kumar, J)

ranjan/-

AFR/NAFR	NAFR
CAV DATE	NA
Uploading Date	
Transmission Date	NA

